विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	..	vii
कार्यकारी सारांश	..	ix
प्रथम अध्याय : विहगांवलोकन		
राज्य का पार्श्व दृश्य	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	3
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	5
प्रतिवेदन संरचना	1.3	6
शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहगांवलोकन	1.4	6
बजटीय प्रक्रियायें	1.5	8
वित्त का आशुचित्र	1.5.1	9
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र	1.5.2	9
राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.6	10
राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन	1.6.1	10
वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे	1.6.2	12
घाटा/आधिक्य	1.6.3	13
घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ	1.6.4	13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.7	14
लेखापरीक्षा के बाद–घाटा/आधिक्य	1.7.1	15
लेखा परीक्षा के बाद–कुल ऋण/दायित्व	1.7.2	16
द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	17
निधियों के स्रोत और उपयोग	2.2	17
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि	2.3.2.1	20
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	21
स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	22
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2.3.3.2	23
करेत्तर राजस्व	2.3.3.3	23
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	2.3.3.4	24
भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.3.5	24
पंद्रहवे वित्त आयोग अनुदान	2.3.3.6	25
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3.7	26
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	27
संसाधनो का उपयोग	2.4	27
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	27
राजस्व व्यय	2.4.2	29
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	30
प्रतिबद्ध एवं गैर–प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	31
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता	2.4.2.3	32
सब्सिडी	2.4.2.4	33
राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	33

	कंडिका	पृष्ठ
पूँजीगत व्यय	2.4.3	34
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	35
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	35
अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरूद्ध	2.4.3.3	37
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	38
उद्देश्य शीर्ष वार व्यय	2.4.5	39
लोक लेखा	2.5	39
शुद्ध लोक लेखा	2.5.1	39
आरक्षित निधि	2.5.2	40
संचित निक्षेप निधि	2.5.3	41
राज्य आपदा राहत निधि	2.5.4	41
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.5.5	42
ऋण प्रबंधन	2.6	42
ऋण घटक का रूपरेखा	2.6.1	43
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना	2.6.2	45
ऋण की रूपरेखाः परिपक्वता और अदायगी	2.6.3	46
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	47
राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता	2.7.1	47
उधार ली गई निधि का उपयोग	2.7.2	47
प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएँ	2.7.3	48
रोकड़ शेष की प्रबंधन	2.7.4	49
निष्कर्ष	2.8	50
अनुशंसाएं	2.9	51
तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	53
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.2	53
वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा	3.3	54
जेण्डर बजट	3.3.1	54
युवा बजट	3.3.2	54
कृषि बजट	3.3.3	55
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं	3.3.4	55
विनियोग लेखा	3.4	55
विनियोग लेखों का सारांश	3.4.1	55
बजटीय निधि का उप–युक्ततम उपयोग	3.4.2	56
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ	3.5	57
विधि के प्राधिकार के बिना व्यय	3.5.1	57
राजस्व व्यय के रूप मे पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरणं	3.5.2	57
अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान	3.5.3	58
अनावश्यक एवं अत्याधिक पुनिर्विनियोग	3.5.4	60
उप–शीर्षो के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	3.5.5	60
बृहद बचत/समर्पण	3.5.6	61
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या	3.5.7	62
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	3.5.8	63
व्यय की अतिवेग	3.6	64
उप–शीर्ष (योजनाएँ) जहाँ मार्च 2021 में पूरा व्यय किया गया था	3.6.1	65

	कंडिका	पृष्ठ
निष्कर्ष	3.7	66
अनुशंसाएं	3.8	66
चतुर्थ अध्याय : लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	67
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब	4.2	67
लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	4.3	69
लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.4	70
उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.5	70
व्यक्तिगत जमा खातें	4.6	71
व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ	4.6.1	72
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	4.6.2	73
केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेन–देन के लेखाएँ	4.7	73
अधोसंरचना विकास कोष	4.7.1	73
पर्यावरण कोष	4.7.2	74
राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधि	4.8	74
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	4.8.1	74
लघु शीर्ष–800 में समायोजन	4.9	76
लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रायल्टी की बुकिंग	4.9.1	78
विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना	4.10	78
रोकड़ शेष का मिलान	4.11	80
भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.12	80
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	4.13	81
हानि तथा गबन आदि के मामले	4.14	82
ऑफ बजट उधार	4.15	82
सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां	4.16	83
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.17	84
निष्कर्ष	4.18	84
अनुशंसाएं	4.19	85
पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
प्रस्तावना	5.1	87
सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	87
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	87
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.4	88
सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	88
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	5.6	89
इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण	5.6.1	89
सम्पत्तियों की पर्याप्तता	5.6.2	90
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना	5.6.3	90
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	91
पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ	5.7.1	91
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.7.2	91
ऋण का भुगतान	5.8	92
ब्याज कवरेज अनुपात	5.8.1	92
सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता	5.9	93
अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)	5.9.1	93

	कंडिका	पृष्ठ
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.9.2	93
निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर	5.9.3	94
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	5.9.4	94
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.10	95
वहन की गयी हानियाँ	5.10.1	95
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण	5.10.2	96
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका	5.11	96
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.11.1	96
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11.2	97
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	97
समय पर प्रस्तुतीकरण की आवष्यकता	5.12.1	97
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता	5.12.2	98
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की निगरानी लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	98
वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा	5.13.1	98
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.2	99
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम	5.14	99
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेंत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.14.1	99
सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रुप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	5.14.2	100
लेखामानकों/भारतीय लेखा मानको के प्रावधानो का अनुपालन न करना	5.15	101
प्रबंधन पत्र	5.16	101
निष्कर्ष	5.17	102
अनुशंसाएं	5.18	103

विषय सूची		
परिशिष्ट का नाम	**परिशिष्ट**	**पृष्ठ**
राज्य की रूपरेखा	1.1	105
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	106
वर्ष 2020–21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है	3.1	109
वर्ष 2020–21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है	3.2	110
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नही हुआ	3.3	112
मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.4	113
उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नही हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)	3.5	115
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)	3.6	118
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)	3.7	120
माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण	3.8	121
उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	3.9	123
वर्ष 2000–01 से 2019–20 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय	3.10	126
वर्ष 2020–21 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ	3.11	127
उप–शीर्ष (योजना), जहाँ पूरा व्यय मार्च 2021 में किया गया	3.12	128
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	4.1	129
31 जनवरी 2021 तक की लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण	4.2	130
लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	4.3	131
लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण	4.4	132
चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	4.5	133
सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण (31 मार्च 2021 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)	4.6	134
विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण	4.7	135
पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2021 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1	136
31 मार्च 2021 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.2	137
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना	5.3	141